प्रस्ताव

31 राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

31

राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

- राज्य के बजट का दो साल का चक्र स्थापित करता है।
- विधानमंडल को $25 मिलियन से अधिक के खर्च तैयार करने से प्रतिबंधित करता है जब तक खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व या खर्च में कटौतियों की पहचान न कर ली जाए।
- गवर्नर को घोषित राजस्व संबंधी आपातस्थितियों के दौरान एकतरफा ढंग से बजट में कटौती करने की अनुमति देता है यदि विधानमंडल कार्य करने में विफल रहता है।
- राज्य के सभी कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की मांग करता है।
- राज्य और स्थानीय बजटों में प्रदर्शन लक्ष्यों की मांग करता है।
- विधान-संबंधी वोट से कम से कम तीन दिन पहले बिल प्रकाशित करने की मांग करता है।
- स्थानीय सरकारों को इस बारे में परिवर्तन करने की अनुमति देता है कि राज्य द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले कानून उन पर कैसे लागू होते हैं, जब तक विधानमंडल या राज्य एजेंसी 60 दिनों के अंदर परिवर्तन को वीटो नहीं कर देते हैं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- राज्य बिक्री कर राजस्व में लगभग $200 मिलियन सालाना की कमी, और कुछ स्थानीय सरकारों के लिए धन में अनुरूप वृद्धि।
- राज्य और स्थानीय खर्च और राजस्व में अन्य, संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी मात्रा सरकारी अधिकारियों द्वारा भविष्य के फैसलों पर निर्भर करेगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अवलोकन

यह उपाय स्थानीय सरकारों, विधायिका, और गवर्नर की कुछ जिम्मेदारियों में बदलाव करता है। यह राज्य और स्थानीय सरकार के संचालनों के कुछ पहलूओं में भी बदलाव करता है। चित्र 1 में उपाय के मुख्य प्रावधानों का सारांश दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा नीचे दी गयी है।

स्थानीय सरकार की योजनाओं को अधिकृत और वित्तपोषित करता है

प्रस्ताव

स्थानीय सरकारों को नयी योजनायें विकसित करने की अनुमति देता है। इस उपाय के तहत काउंटी और अन्य स्थानीय सरकारें (जैसे शहर, स्कूल जिले, सामुदायिक कॉलेज जिले, और विशेष जिले) यह समन्वय करने के लिये योजनायें तैयार कर सकते हैं कि वे जनता को सेवायें कैसे उपलब्ध करायें। योजनाएं इस बात को भी संबोधित कर सकती है कि स्थानीय सरकारें अनेक क्षेत्रों में सेवाओं को कैसे दें, जिसमें आर्थिक विकास, शिक्षा सामाजिक सेवायें, सार्वजनिक सुरक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। प्रत्येक योजना को (1) काउंटी (2) काउंटी के छात्रों में से अधिकांश स्कूल जिले और (3) काउंटी की जनसंख्या के अधिकांश का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थानीय सरकारों के प्रशासन मंडलों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। स्थानीय एजेंसियों को योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य से वित्तपोषण प्राप्त होगा (नीचे दिये वर्णन के अनुसार)।

स्थानीय सरकारों को नयी योजनायें विकसित करने की अनुमति देता है। यदि स्थानीय सरकारों को लगता है कि राज्य का कानून या विनियम उनकी योजना को चलाने की क्षमता को प्रतिबाधित करते हैं तो वे स्थानीय प्रक्रियाओं का विकास कर सकते हैं जो मौजूदा राज्य के कानून या विनियम के उद्देश्यों के क्रियात्मक समकक्ष हैं। स्थानीय सरकारें राज्यों द्वारा वित्त पोषित के कार्यक्रमों का प्रशासन करने में—राज्य के

कानूनों या विनिमयों के बजाय—इन स्थानीय प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकती हैं। विधायिका (राज्य कानूनों के मामले में) या संबंधित राज्य विभाग (राज्य विनियमों के मामले में) के पास इन वैकल्पिक स्थानीय प्रक्रियाओं को अस्वीकार करने का अवसर होगा। स्थानीय रूप से विकसित प्रक्रियायें चार साल के बाद समाप्त हो जायेंगी बशर्ते समान प्रक्रिया के माध्यम से उनका नवीकरण न किया जाये।

स्थानीय संपत्ति-करों के हस्ताँतरण की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया के करदाता स्थानीय सरकारों को सालाना संपत्ति करों के रूप में लगभग $50 बिलियन का भुगतान करते हैं। राज्य के कानून प्रशासित करते हैं कि संपत्ति करों को प्रत्येक काउंटी की स्थानीय सरकारी संस्थाओं में किस प्रकार बाँटा जाना है। यह उपाय स्थानीय सरकारों को उनको आवंटित संपत्ति करों को अपने बीच अपने द्वारा चयनित किसी तरह से हस्ताँतरित करने के लिए योजनाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। प्रत्येक प्रभावित स्थानीय सरकार को परिवर्तन को अपने प्रशासन मंडल के दो तिहाई मतों से स्वीकृत कराना होगा।

कुछ राज्य बिक्रीकर राजस्व को स्थानीय सरकार को हस्ताँतरित करता है। वर्तमान में, राज्य में औसत बिक्री कर की दर सिर्फ 8 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है। इससे राज्य और स्थानीय सरकार के बीच लगभग बराबर आवंटित राजस्वों के साथ 2009–10 में $42.2 बिलियन एकत्र किये गए। वित्तीय वर्ष 2013–14 में शुरू होकर ये उपाय राज्य के हिस्से के एक छोटे भाग को उन काउंटियों को हस्ताँतरित करेंगे जो नयी योजनाओं को लागू करते हैं। इससे करदाताओँ द्वारा भुगतान किये जाने वाले बिक्रीकरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हस्तांतरण से योजनाओं वाली काउंटियों में भाग लेने वाली स्थानीय सरकारों के राजस्व में कुछ ही समय में सालाना लगभग $200 मिलियन की वृद्धि होगी। राज्य सरकार को उसी राशि का घाटा होगा जो अब राज्य कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध नहीं होगी। बिक्रीकर भाग लेने वाले काउंटियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित किये जायेंगे। उपाय के लिए एक स्थानीय योजना आवश्यक है ताकि इनका और अन्य निधियों का वितरण उपलब्ध कराया जा सके जिनका मंतव्य स्थानीय योजना को लागू करने में समर्थन करना है।

चित्र 1

प्रस्ताव 31 के मुख्य प्रावधान

✓ **स्थानीय सरकारी योजनाओं को अधिकृत करता है और वित्तपोषण उपलब्ध कराता है**
- राज्य के राजस्वों को उन काउंटियों को हस्ताँतरित करता है जिनमें स्थानीय सरकारें अपनी सावर्जनिक सेवाओं का समन्वय करने के लिए योजनाओं को लागू करती हैं।
- इन राज्य सरकारों को राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करने की अनुमति देता है।
- इन स्थानीय सरकारों को स्थानीय संपत्ति करों को अपने बीच हस्ताँतरित करने की अनुमति देता है।

✓ **कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है**
- कुछ अधिनियमों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है। जो राज्य की लागतों को बढ़ाते हैं या राजस्व को घटाते हैं। जब तक की वित्तपोषण के नये स्त्रोत और/या खर्च में कटौतियों की पहचान नहीं कर ली जाती।
  - विभिन्न प्रकार के बिलों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट देता है।
- विधायी अनुमोदन से कम से कम 3 दिन पहले सभी बिलों और संशोधनों को जनता के लिए उपलब्ध कराने को आवश्यक बनाता है।

✓ **राज्य के खर्च में कटौती करने की गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है**
- कुछ दशाओं में राज्य वित्तीय आपातकाल में खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर को अनुमति देता है।

✓ **सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण करने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करता है**
- सालाना बजट प्रक्रिया को एक 2 वर्षीय राज्य बजट प्रक्रिया में बदलता है।
- सावर्जनिक कार्यक्रमों के विधायी निरीक्षण के लिए प्रत्येक 2 वर्षीय सत्र के हिस्से को अलग करने के लिए विधायिका से अपेक्षा करता है।
- राज्य और स्थायी सरकारों से कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और यह व्याख्या करने की, कि उनके बजट विभिन्न उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, अपेक्षा करता है।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।

वित्तीय प्रभाव

ऊपर वर्णित $200 मिलियन को हस्ताँतरित करने के अतिरिक्त राज्य और स्थायी सरकारों पर अन्य वित्तीय प्रभाव भी होंगे। उदाहरण के लिए, स्थानीय सरकारों को राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों का प्रशासन करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने की अनुमति से काफी महत्तपूर्ण रूप से भिन्न कार्यक्रम परिणाम आते हैं और राज्य या स्थायी लागत, जो अन्यथा होती। स्थानीय सरकारों को संपत्ति करों का हस्ताँतरण करने की अनुमति से प्रभाव पड़ सकता है कि किसी स्थानीय सरकार को कितना पैसा जाता है, परन्तु इससे संपत्ति करदाताओं द्वारा कुल भुगतान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभवतः स्थायी सरकार नयी योजनाओं को तैयार करने और उनका प्रशासन करने के लिए एक छोटी अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। उपाय के इस भाग के कारण होने वाले परिवर्तन इन पर निर्भर करेंगे (1) कितने काउंटी योजनायें तैयार करते हैं। (2) कितनी स्थानीय सरकारें उस तरीके में परिवर्तन करती हैं जो राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों का प्रशासन करता है और (3) उनकी गतिविधियों के परिणाम। उन कारणों के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए इस उपाय के राजस्व प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ काउंटियों में यह प्रभाव महत्तवपूर्ण हो सकते हैं।

कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है

वर्तमान कानून

बजट और अन्य बिल। प्रत्येक वर्ष विधायिका और गवर्नर राज्य बजट बिल और अन्य बिलों को अनुमोदित करते हैं। बजट बिल सामान्य फंड से और अन्य अनेकों राज्य खातों से खर्च की अनुमति देता है। (सामान्य फंड राज्य का मुख्य ऑपरेटिंग खाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं, जेलों, और अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराता है)। सामान्य रूप से, विधायिका के दोनों सदनों (सीनेट और असेंबली) का बहुमत मतदान बजट बिल और अन्य अधिकांश बिलों के अनुमोदन के लिए आवश्यक होता है। हालाँकि राज्य करों में वृद्धि करने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई मत आवश्यक है।

नये कानूनों पर विचार करने की अपनी सामान्य प्रक्रिया के भाग के रूप में, विधायिका और गवर्नर प्रस्तावित कानून के राज्य के व्यय और राजस्व पर पड़ने वाले अनुमानों की समीक्षा करते हैं। जहाँ राज्य का संविधान यह स्थापित नहीं करता है कि राज्य पहचान करे की प्रत्येक नये कानून का वित्तपोषण किस प्रकार किया जायेगा, यह आवश्यक है कि राज्य का कुल बजट संतुलित किया जाये। विशेषकर, रूप से प्रत्येक वर्ष जब राज्य अपना बजट अपनाता है, तो राज्य को दिखाना होगा कि सामान्य फंड के राजस्व अनुमोदित सामान्य व्यय या तो पूरा करेंगे या अससे अधिक होंगे।

प्रस्ताव

राज्य की लागतों को बढ़ाने की विधायिका की क्षमता को सीमित करता है। इस उपाय के लिए आवश्यक है कि विधायिका दिखाये कि कुछ बिल, जो किसी वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यय में $25 मिलियन से अधिक की वृद्धि करते हैं, उनका भुगतान खर्च में कटौतियों, राजस्व में बढ़ोत्तरी या दोनों के संयोजन से किया जायेगा। यह आवश्यकता उन बिलों पर लागू होती है जो नये राज्य विभागों या कार्यक्रमों का सृजन करते हैं, वर्तमान राज्य विभागों या कार्यक्रमों का विस्तार करते हैं या राज्य अधिकृत स्थानीय कार्यक्रमों का सृजन करते हैं। इन आवश्कताओं से छूट में वे बिल शामिल हैं जो राज्य के विभाग या कार्यक्रम के लिए एक बार के खर्च की अनुमति देते हैं, कार्य भार या जीवनयापन की लागत में वृद्धि के कारण किसी विभाग या कार्यक्रम के वित्तपोषण में वृद्धि करते हैं, संघीय कानून द्वारा आवश्यक वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं या सामूहिक सौदेबाजी अनुबन्ध के अनुसार राज्य के कर्मचारियों के वेतन या अन्य मुआवजे में वृद्धि करते हैं। यह उपाय उन बिलों को भी छूट देता है जो 2008–09 के बाद राज्य के बजट को संतुलित करने में मदद करने के लिए किसी वर्ष में उन राज्य के कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण को बहाल करते हैं।

राज्य के राजस्वों को घटाने की विधायिका की क्षमता को सीमित करता है। इस उपाय की यह भी आवश्यकता है कि विधायिका यह भी दिखाये कि जो बिल राज्य के करों या अन्य राजस्वों में किसी वित्तीय वर्षों में $25 मिलियन से अधिक की कमी करते हैं उनका भुगतान खर्च में कटौती, राजस्व में बढ़ोत्तरी, या दोनों के संयोजन से किस प्रकार किया जायेगा।

जब विधायिका बिलों को पारित कर सकती है तो परिवर्तित हो जाता है। यह उपाय अन्य परिवर्तनों को करता है जो विधायिका के बिलों को पारित किये जा सकने पर प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, इस उपाय की आवश्यकता है कि विधायिका बिलों को और उनमें किए जाने वाले संशोधनों को पारित करने से पहले कम से कम 3 दिनों के लिए जनता को उपलब्ध कराये (केवल कुछ बिलों को छोड़कर जो प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमलों से संबंधित होते हैं)।

वित्तीय प्रभाव

यह उपाय विधायिका के लिए ऐसे कुछ बिलों को पारित करना कठिन बना देगा जो राज्य के व्यय में वृद्धि करते हैं या राज्स्व में कमी करते हैं। इस प्रकार विधायिका की क्षमता को सीमित करने के परिणामस्वरूप सावर्जनिक सेवाओं पर राज्य की निधि को खर्च करने में कमी आ सकती है—या कर या शुल्क अधिक हो सकते हैं—उसके मुकाबले जो अन्यथा होते। क्योंकि इस उपाय के इस भाग का वित्तीय प्रभाव विधायिका के भविष्य के निर्णयों पर निर्भर करता है, इस प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि राज्य स्थानीय सरकारों को वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं, इसलिए समय के साथ उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

राज्य के खर्चे घटाने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है।

वर्तमान कानून

प्रस्ताव 58 (2004) के तहत बजट बिल स्वीकृत हो जाने के बाद गवर्नर यदि यह निर्धारित करते हैं कि राज्य विशाल राजस्व कमी या अत्याधिक खर्च का सामना कर रहा है तो वह राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो गवर्नर को विधायिका का विशेष सत्र बुलाना होगा और वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए कार्यवाईयों का प्रस्ताव देना होगा। विधायिका के पास अपने जवाब पर विचार करने के लिए 45 दिन का समय होता है। हालाँकि राज्य के खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर की शक्तियाँ वर्तमान में बहुत सीमित हैं, भले ही विधायिका 45 दिन की अवधि में कोई कार्यवाही न करे।

प्रस्ताव

विशेष परिस्थितियों में खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर को अनुमति देता है। इस उपाय के तहत, यदि विधायिका 45 दिनों के भीतर वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए कानून पारित नहीं करती है तो गवर्नर सामान्य फंड से खर्च में कुछ कटौती कर सकते हैं। गवर्नर उस खर्च में कटौती नहीं कर सकते हैं जो संविधान या संघीय कानून के तहत आवश्यक है—जैसे अधिकांश स्कूल खर्च, ऋण सेवायें, पेंशन योगदान, और स्वास्थ्य एवं समाज सेवा कार्यक्रमों पर कुछ खर्च। (सामान्य फंड में से खर्च अधिकांश वर्तमान में इन्ही श्रेणियों पर होता है।) कटौतियों की कुछ राशि बजट को संतुलित करने की आवश्यक राशि से अधिक नहीं हो सकती। विधेयक अपने दोनों सदनों में दो तिहाई मतदान से सभी कटौतियों या इनके कुछ भागों को ओवरराइड करने का निश्चय कर सकता है।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।

वित्तीय प्रभाव

खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करने के परिणामस्वरूप राज्य का कुछ खर्च उससे कम हो सकता है जितना यह अन्यथा होता। इस परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु कुछ सालों में यह महत्वपूर्ण हो जायेगा। स्थानीय सरकारी बजटों पर भी कम राज्य खर्च से प्रभाव पड़ेगा।

सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है।

प्रस्ताव

सालाना राज्य बजट प्रक्रिया को दो वर्षीय प्रक्रिया में बदलता है। यह उपाय राज्य बजट प्रक्रिया को एक वर्षीय (सालाना) से दो वर्षीय प्रक्रिया में बदलता है। 2015 से शुरू होकर, हर दूसरे वर्ष गवर्नर आने वाले दो वित्तीय वर्षों के लिए बजट प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए, जनवरी 2015 में गवर्नर जुलाई 2016 में शुरू होकर हर दूसरे वर्ष गवर्नर एक प्रस्तावित बजट अध्यतन प्रस्तुत कर सकते हैं। 2016 में शुरू करते हुए हर दो साल, राज्यपाल एक प्रस्तावित बजट अद्यतन प्रस्तुत सकता है। यह उपाय बजट बिल को पारित करने के लिए विधायिका की वर्तमान 15 जून की संवैधानिक समय सीमा में परिवर्तन नहीं करता है।

सावर्जनिक कार्यक्रमों के विधायिका निरीक्षण के लिए विशिष्ट समय अवधि को खारिज करता है। वर्तमान में विधायिका अपने दो वर्षीय सत्र में विभिन्न समयों पर राज्य और स्थायी कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और उनकी पर्यवेक्षण करती है। इस उपाय की आवश्यकता है कि—सत्र के दूसरे वर्ष में जुलाई से शुरू होकर—विधायिका अपने दो वर्षीय सत्र के एक हिस्से को सावर्जनिक कार्यक्रमों के निरीक्षण और समीक्षा के लिए आरक्षित करे। विशेष रूप से इस उपाय की आवश्यकता है कि विधायिका एक प्रक्रिया तैयार करे और प्रत्येक राज्य वित्तपोषित कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करे—चाहें वह राज्य द्वारा प्रतिबंधित हो या स्थानीय सरकार द्वारा—हर पांच साल में कम से कम एक बार। यह निरीक्षण करने के दौरान विधायिका उन बिलों को छोड़कर जो (1) तुरन्त प्रभावी हो जाते हैं (जिनके लिए आमतौर पर दोनों सदनों के दो तिहाई मतों की आवश्यता होती है) (2) गवर्नर के वीटो को ओवरराइड करता है (जिसके लिए दोनों सदनों के दो तिहाई मतों की आवश्यता होती हैं) बिलों को पारित नहीं कर सकती है।

नयी राज्य एवं स्थानीय बजट बनाने की आवश्यकताओं को लागू करता है। वर्तमान में राज्य और स्थायी सरकारों के पास यह निर्धारित करने में व्यापक लचीलापल है कि उनके सावर्जनिक कार्यक्रमों के संचालनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाये। यह उपाय राज्य और स्थायी सरकारों के लिए अपने बजटों में नयी मदों को शामिल करने के लिए कुछ सामान्य आवश्यकताओं को लागू करता है। विशेष रूप से, सरकारों को अपने कार्यक्रमों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना है और व्याख्या करनी है कि उनके बजट विभिन्न उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं। राज्य और स्थायी सरकारों को इन उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी प्रगति पर रिपोर्ट देनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

राज्य और स्थायी सरकारों को नयी बजटिंग आवश्यकताओं को लागू करने के लिए प्रणाली को स्थापित करने और नयी मूल्यांकन आवश्यकताओं को लागू करने में बढ़ी हुई लागतों का अनुभव होगा। ये लागतें इस बात पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होंगी कि राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने आवश्यकताओं को किस प्रकार लागू किया । पूरे राज्य में, लागत **सालाना तौर पर मिलियनों से लेकर दसों मिलियन डॉलर के बीच** हो

सकती है जो समय के साथ स्थिर होती जायेगी। ये नयी बजटिंग और मूल्यांकन आवश्यकताएं विभिन्न तरीकों—जैसे व्यय का पुनर्नियोजन, कार्यक्रम की दक्षता और कुछ कार्यक्रम क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश में निर्णय करने को प्रभावित कर सकती है। सरकारों पर वित्तीय प्रभावों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

उपाय के वित्तीय प्रभावों का सारांश

चित्र 2 में दिये गये साराँश के अनुसार कुछ राज्य बिक्री कर राजस्वों को काउंटियों में हस्तांतरित करता है जो स्थानीय योजनाओं को लागू करती है। इस हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में सालाना $200 मिलियन की कमी आयेगी, और उन काउंटियों में स्थानीय सरकारों को फंडिंग में संबंधित बढ़ोतरी होगी। इस उपाय की अन्य स्थितियों और स्थानीय वित्त परिवर्तनों का शुद्ध प्रभाव आमतौर पर सावर्जनिक अधिकारियों के भविष्य पर निर्भर करेगा और इस कारण इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। दीर्घकाल में राज्य और स्थानीय व्यय या राजस्व में ये अन्य परिवर्तन उपरोक्त वर्णित $200 मिलियन के बिक्री कर हस्तांतरण से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

चित्र 2

प्रस्ताव 31 के मुख्य वित्तीय प्रभाव

	राज्य सरकार	स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारी योजना का वित्तपोषण और प्राधिकरण करता है		
योजनाओं के लिए वित्तपोषण	राजस्व में $200 मिलियन की कटौती।	योजनाओं का विकास करने वाले काउंटी में स्थानीय सरकारों को राजस्व में $200 मिलियन की सालाना वृद्धि।
नई योजनाओं पर प्रभाव	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु काफी महत्वपूर्ण।	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ काउंटी में काफी महत्वपूर्ण।
कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है	संभावित रूप से कम खर्च—या अधिक राजस्व—विधायिका की भविष्य कार्रवाईयों के आधार पर।	विधायिका की भविष्य कार्रवाईयों के आधार पर स्थानीय कार्यक्रमों के लिए राज्य वित्तपोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
राज्य के खर्चे घटाने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है	संभावित रूप से कुछ सालों में कम खर्च।	कुछ सालों में स्थानीय कार्यक्रमों के लिए काफी कम राज्य वित्तपोषण।
सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है		
कार्यान्वयन लागत	सालाना संभवतः मिलियनों से दसियों मिलियन डॉलर, समय के साथ स्थिर।	सालाना संभवतः मिलियनों से दसियों मिलियन डॉलर, समय के साथ स्थिर।
नई आवश्यकताओं का प्रभाव	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।